



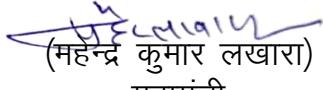
अंग्रेजी माध्यम का विभेद समाप्त कर समान रूप से पद आवंटन, प्रारम्भिक शिक्षा से सेटअप परिवर्तन 6 डी तथा अन्य नियमान्तर्गत अनिवार्य के स्थान पर स्वैच्छिक करने पर विस्तृत वार्ता हुयी।

### इन पर बनी सैद्धान्तिक सहमति

सर्धेर्ष समिति संयोजक सम्पत्ति सिंह ने बताया कि शिक्षा सचिव से हुई वार्ता में सहायक कर्मचारियों के सन्दर्भ में वैकल्पिक साधन के साथ व्यवस्था करवाने, निदेशालय स्तर पर शिक्षकों के लम्बे समय से लम्बित विभागीय जाँच, एसीपी अवकाश स्थायीकरण प्रकरणों के सन्दर्भ में निदेशालय अधिकारियों से जल्द ही संवाद कर समयबद्ध सीमा तय करवाने, पंचायतों के पुनर्गठन के करवाने पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को देने, तृतीय, द्वितीय श्रेणी व व्याख्याता सर्वंग के शिक्षकों के बकाया नोशनल लाभ प्रकरणों एवं एसीपी के समय नोशनल दिनांक से परिलाभ के सन्दर्भ में आवश्यक परीक्षण करवाने तथा राज्य में एक समान नीति निर्देश जारी करवाने, काउसलिंग पद्धति को युक्तियुक्त पारदर्शिता के साथ लागू करने की दृष्टि से 48 घण्टे पूर्व समस्त रिक्त पदों को प्रदर्शित करने, ग्रीष्मावकाश समय के बकाया वेतन का परीक्षण करवाने की बात कही। शाला दर्पण पोर्टल की सर्वर क्षमता को बढ़ाने को प्रक्रियाधीन, ग्रीष्मावकाश समय के बकाया वेतन का परीक्षण करवाकर युक्तिसंगत निर्देश देने, गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त करने पर धैर्यता रखने, टीएसपी नोन टीएसपी क्षेत्रों के शिक्षकों को गृह जिले में लगाने पर विभागीय अधिकारियों से विचार कर कार्यवाही करने, नवक्रमोन्त विद्यालयों में पूर्व से पदस्थापित शिक्षकों के समायोजन विभागीय दिशा निर्देशों अनुरूप जल्द ही करने, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के पदस्थापन हेतु छात्र संख्या की अनिवार्यता पर परीक्षण करवाने, उदयपुर सभांग की 19–20 के बकाया पदस्थापन हेतु सम्बन्धित अधिकारियों से तथ्यात्मक जानकारी कर आवश्यक कार्यवाही करने, निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को निदेशालय स्तर की समस्याओं के निस्तारण हेतु दूरभाष से निर्देशित किया तथा साथ ही कई बिन्दुओं पर सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देशों के साथ कार्यवाही करवाने पर सैद्धान्तिक सहमति दीं।

### मुख्यमंत्री सचिव से भी हुई चर्चा

प्रदेश सभाध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि तृतीय श्रेणी के स्थानांतरण को एवं संगठन की 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के सचिव ललित कुमार से चर्चा हुई जिस पर उन्होंने कहा कि जल्द स्थानांतरण एवं अन्य कार्रवाई के लिए फाइल मुख्यमंत्री महोदय के सामने प्रस्तुत कर दी जाएगी।

  
(महेन्द्र कुमार लखारा)  
महामंत्री